Utilisation of Funds ARWSP

6534. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the benefits under the Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) fund have been fully utilised by the persons belonging to Scheduled Castes/Tribes during the last three years;

(b) if so, what are the details thereof; and

c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) The funds under Accelerated Rural Water Supply Programme are not released to the individuals directly by the Central Government but to the State Government for implementation of Rural Water Supply Schemes. However, 25% and 10% of the funds are to be utilised by the State Government for providing drinking water facilites for Scheduled Castes & Scheduled Tribes population in rural areas respeetively.

(b) and (c) About 73% SC and 89.5% of ST population have been provided with safe drinking water facilities so far.

ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना

6535. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों, विशेषकर कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन करने हेतु अन्य संबंधित विभागों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक विभाग की क्या-क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) से (घ) जहां तक ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय का संबंध है, मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों अथवा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। लेकिन समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जिला स्तर पर ढांचा निधियों के 10% का समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लाभार्थियों के लिए ढांचा सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने और उनमें सुधार करने हेतु उपयोग करने का प्रावधान किया गया है। तथापि उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग एवं कृषि तथा ग्रामोद्योग विभाग से इस संबंध में जानकारी मांगी गई थी। उस मंत्रालय ने भी सूचित किया है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों, विशेष रूप से कुटीर उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा सुविधाएं देने के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई है। तथापि, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशेड स्थापित करने के लिए सहायता देता है। इसके अतिरिक्त खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 10 उत्पादन-सह-प्रशिक्षण केन्द्रों के अलावा, 22 विभागीय और 21 गैर-विभागीय बहु आयामी प्रशिक्षण केन्द्रों की मार्फत कारीगरों और पर्यवेक्षक स्तर के तकनीकी कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत गुजरात को आवंटित की गई धनराशि

6536. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान गुजरात को जिले-वार रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई और तत्कालीन सरकार द्वारा वास्तविक रूप से कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई;